'माँ योजना सुदृढ़ होगी, क्लेम रिजेक्शन न्यूनतम स्तर पर लाएंगे : वी. श्रीनिवास

मुख्य सचिव ने की चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (माँ योजना) को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ, ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधारभूत ढांचे को भी और मजबूत किया जाएगा। आमजन को रोगों से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की।

- वी. श्रीनिवास ने टीबी उन्मूलन एवं माँ योजना के क्रियान्वयन को सराहा

उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी एवं विजनरी योजना है, जिसके माध्यम से करीब 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। देशभर में यह अपनी तरह की अनूठी योजना है, जिसमें सामान्य रोगों से लेकर ट्रांसप्लांट तक के जटिल रोगों का नि:शुल्क उपचार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना में इंश्योरेंस कम्पनियों के साथ समन्वय और बेहतर किया जाए, जिससे रोगियों को उपचार लेने में और अधिक सुगमता हो।

एनएचए की बेस्ट प्रैक्टिसेज अपनाएं

मुख्य सचिव ने कहा कि माँ योजना के तहत बड़ी संख्या में रोगी राजकीय चिकित्सा संस्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से राजकीय अस्पतालों में क्लेम रिजेक्शन अधिक रहता है, इसे न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए जाएं। बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर क्लेम संबंधी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने योजना को और सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को अपनाने के निर्देश दिए।

भवनों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग हो

बैठक में मुख्य सचिव ने पीएम-अभीम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना के तहत निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता एवं समुचित उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों के दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण, नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, जहां आवश्यक हो वहां आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए कार्य किए जाएं तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ एवं बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

प्रदेश में टीबी से मृत्यु दर घटाने के निर्देश

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है, लेकिन हमें सतत प्रयासों से टीबी से होने वाली मृत्यु दर को 1 प्रतिशत तक लाना है। इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि टीबी मुक्त राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए आईईसी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। उन्होंने अभियान के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले पोषण किट की व्यवस्था की भी जानकारी ली।

''माँ योजना'' का लगातार दायरा बढा

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि माँ योजना का दायरा पिछली स्वास्थ्य बीमा योजना की अपेक्षा काफी बढ़ाया गया है। इसमें अब पहले से ज्यादा पैकेज और पहले से ज्यादा अस्पतालों का नेटवर्क उपलब्ध है। साथ ही, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी प्रारंभ होने से देश के 30 हजार से अधिक अस्पतालों में प्रदेश के नागरिक उपचार ले सकते हैं। योजना का राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रभावी संचालन होने से आमजन निजी अस्पतालों की अपेक्षा सरकारी अस्पतालों में उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं।

पीएम-अभीम में 94 प्रतिशत व्यय हुआ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि पीएम-अभीम के तहत प्रदेशभर में नव स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है। इसके चलते योजना के तहत आवंटित राशि का अधिकतम व्यय सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत प्राप्त राशि में से रिकॉर्ड 94 प्रतिशत राशि व्यय की गई।

19.38 लाख मरीजों को कैशलेस इलाज मिला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, हजारी लाल अटल ने बताया कि मा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.38 लाख मरीजों को 3888 करोड़ रूपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश की 6547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। बैठक में राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

किन्नर अखाड़े से जुड़े बाउंसरों ने एडवोकेट से मारपीट-लूटपाट की

- चिंकारा कैंटीन के पास मामूली विवाद के बाद हुए इस हमले में एडवोकेट का सिर फूटा
- बाउंसरों ने मौके पर मौजूद एक होमगार्ड जवान को भी धमकाकर वीडियो डिलीट कराया
- वकील की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त कर चार लोगों को राउंडअप किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी के बनीपार्क इलाके में मंगलवार सुबह किन्नर अखाडा से जुड़े काफिले के बाउंसरों द्वारा एक एडवोकेट के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। चिंकारा कैंटीन के पास मामूली विवाद के बाद हुए इस हमले में एडवोकेट का सिर फूट गया, वहीं मौके पर मौजूद एक होमगार्ड जवान को भी धमकाकर वीडियो डिलीट कराया गया।

पुलिस के अनुसार मानसरोवर के मांग्यावास निवासी एडवोकेट कुणाल शर्मा सुबह करीब 10 बजे सेशन कोर्ट जा रहे थे। चिंकारा कैंटीन की ट्रैफिक लाइट के पास वे अपनी कार पार्क कर रहे थे, तभी मध्यप्रदेश नंबर की छह लग्जरी गाडियां तेज रफ्तार से सीकर रोड की ओर जा रही थीं। इसी दौरान एक गाडी ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि टक्कर के बाद काफिले की सभी गाडियां रुक गईं। बातचीत के लिए नीचे उतरे एडवोकेट पर गाडियों से उतरे 5-6 बाउंसरों ने हमला कर दिया। आरोप है कि बाउंसरों ने नुकीली वस्तु से सिर पर वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और मोबाइल, नकदी व सोने की चेन छीन ली। बीच-बचाव करने आए लोगों और पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की गई।

घटना के दौरान अग्निशमन कार्यालय में तैनात होमगार्ड जवान भूपेंद्र सिंह वीडियो बना रहे थे। बाउंसरों ने उन्हें पकड़कर धमकाया, जबरन गाड़ी में बैठाया और वीडियो डिलीट करवा कर मोबाइल लौटाया।

पीड़ित के अनुसार काफिला किन्नर अखडा उज्जैन के महामंडलेश्वर काली नंद गिरी से जुड़ा था। काफिले में दो डिफेंडर, दो फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो और एक अन्य कार शामिल थी, जिन पर हूटर लगे हुए थे।

घटना की सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम से नाकाबंदी करवाई गई। हरमाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफिले में शामिल एक गाड़ी को जब्त कर उसमें सवार चार लोगों को राउंडअप किया है।

पुलिस में एडवोकेट कुणाल शर्मा सहित अन्य वकीलों की ओर से शिकायत दी गई है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर आरोपियों की भूमिका की पडताल कर रही है।

मालवीय नगर के डी-ब्लॉक में प्याऊ का शुभारंभ

जयपुर। भीषण गर्मी से राहगीरों को पानी पिलाकर राहत प्रदान करने के लिए मालवीय नगर के डी ब्लॉक में मुख्य सड़क पर ठंडी प्याऊ का शुभारंभ हुआ। जेल उपमहानिरीक्षक सुमन मालीवाल ने फीता काटकर कर इसका उद्घाटन किया। समाजसेवी गंगा सहाय प्रजापत ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष प्याऊ लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर निवर्तमान पार्षद गोविन्द छीपा, ओम स्वामी, शैलेष शाह, घीया देवी, कमलेश, विष्णु, रामपाल जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं आमजन उपस्थित रहे।

सार-समाचार

एन.के.शर्मा की पुस्तक का विमोचन

जयपुर। युवा लेखक एवं विचारक एन. के. शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ''प्रेरणा से परिवर्तन की ओर'' का विमोचन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। लेखक एन. के. शर्मा ने पुस्तक की प्रति राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल बागडे ने एन. के. शर्मा को पुस्तक लेखन की बधाई दी और कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पुस्तक की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह पुस्तक निश्चित रूप से युवाओं को उनके जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम के दौरान लेखक की पत्नी माधुरी शर्मा, युविका शर्मा एवं अविका शर्मा भी उपस्थित रहीं।

मोबिक्विक का एनबीएफसी लाइसेंस मंजूर

जयपुर। वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (मोबिक्विक) ग्रुप को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है। इस लाइसेंस के साथ अब एक नया लैंडिंग डिवीजन शुरू किया जाएगा, जिससे रेगुलेटेड लेंडिंग क्षमता बढ़ेगी, नए और इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स निर्मित किए जा सकेंगे और ज्यादा ग्राहकों व मर्चेंट्स तक बेहतर तरीके से सर्विसेस पहुँचाई जा सकेंगी। एनबीएफसी, ग्रुप की अंतर्निहित शक्तियों पर आगे बढ़ेगा, जिसमें 18.6 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस, भरोसेमंद ब्रांड के साथ मजबूत टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क अंडरराइटिंग और कलेक्शन क्षमता भी शामिल है। एमएफएसपीएल के जरिए नए क्रेडिट प्रोडक्ट्स तेजी से लॉन्च किए जा सकेंगे, जो कंज्यूमर्स और एमएसएमई को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट दोनों प्रदान करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान समय में सर्विस की पहुँच सीमित है। यह जानकारी मोबिक्विक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, को-फाउंडर और सीएफओ उपासना टाकू ने दी है।

राज्यपाल और डॉ. मांडविया की भेंट

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

होटल मैरियट व रमाडा सील करने पर निगम आयुक्त और डीसी को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडी टैक्स वसूली को लेकर शहर की मैरियट व रमाडा होटल को सील करने के मामले में जयपुर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर गौरव सैनी, जोन उपायुक्त मुकुट सिंह, रेवेन्यू अधिकारी पवन मीणा व रिकवरी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेन्द्र शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह होटल मालिकों की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम के मालवीय नगर जोन के उपायुक्त ने गत 30 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच जयपुर मैरियट व रमाडा होटल को यूडी टैक्स बकाया बताते हुए सील कर दिया। इस दौरान होटल प्रबंधन ने तत्काल नगर निगम को डिमांड राशि देकर सील खुलवाई। याचिका में कहा गया कि इस मामले में नगर निगम के डिमांड लेटर को होटल मालिकों ने पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी।

जिसमें कहा था कि वे नियमित यूडी टैक्स जमा करा रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने बिना कोई आदेश दिए अतिरिक्त डिमांड लेटर जारी कर दिया। तब हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह कंपनी का प्रतिवेदन सुनकर व दस्तावेजों को देखकर नया आदेश जारी करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रमाडा होटल का मामला 27 व जयपुर मैरियट का मामला 30 मार्च को निगम में सुनवाई के लिए रखा। अदालती आदेश पर रमाडा होटल के प्रतिनिधियों ने 27 मार्च को उपायुक्त के यहां अपना पक्ष रखा, लेकिन नगर निगम ने बिना कोई आदेश दिए 30 मार्च सुबह 7 बजे रमाडा होटल को सील करना शुरू कर दिया। जयपुर मैरियट के मामले में भी सुनवाई की तारीख 30 मार्च थी, तब भी उपायुक्त ने उसी दिन सुबह 9 बजे होटल सील करना शुरू कर दिया। इसे अवमानना याचिका के जरिए खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर व उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। ऐसे में उन्हें दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यशाला

जयपुर। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत् बाल विवाह रोकथाम हेतु राज्य रणनीति एवं कार्ययोजना-2026 विकसित की गयी है। जिसके तहत कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान के माध्यम से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग में नामांकित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का आमुखीकरण प्रशिक्षण करवाया गया। प्रशिक्षणों के पंचम चरण का आयोजन 28 अप्रैल को एचसीएम रीपा जयपुर में हुआ। बाल अधिकारिता विभाग की तकनीकी सहयोग इकाई के तकनीकी सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में जयपुर संभाग के जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनूं एवं भरतपुर संभाग के भरतपुर जिलों के महिला बाल विकास विभाग के नामांकित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों ने भाग लिया।

सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती- 2012 व 2018 में कुछ निकायों को छोडकर अन्य जगहों पर नियुक्ति नहीं देने से जुडे मामले में राज्य सरकार व अन्य से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश इंदरराज निदानिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2012 की भर्ती रद्द करने का आदेश 11 अगस्त, 2014 को वापस लेते हुए राजाखेडा, धौलपुर, कोटा, राजसमंद, टोंक व चूरू में नियुक्ति दे दी और अलवर में भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जयपुर नगर निगम सहित अन्य निकायों में नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में करीब 23,820 सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त है। इसमें राजधानी जयपुर में चार हजार से अधिक पद खाली चल रहे हैं। जिसके चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। गत करीब चौदह साल से वाल्मीकि समाज के आवेदकों को विभिन्न कमेटियों के निर्णयों का हवाला देकर उलझा रखा है। याचिका में कहा गया कि वाल्मीकि समाज की ओर से हडताल किए जाने पर साल 2024 में इन्हें जल्दी नियुक्ति देने का समझौता हुआ था, लेकिन बाद में मनमाने ढंग से भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई और अंतत: उसे वापस ले लिया गया। याचिका में गुहार की गई है कि खाली चल रहे पदों पर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए।

कुंडा की ढाणी में सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र

जयपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंगलवार को जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर के कुंडा की ढाणी में स्थापित हुआ। करीब 4.9 मेगावाट क्षमता का यह सौर ऊर्जा संयंत्र कुंडा की ढाणी विद्युत सब डिविजन के ताला स्थित 33 केवी सब स्टेशन से जुडे गांव डेकला में स्थापित हुआ है। लगभग 24 बीघा भूमि पर फैले इस संयंत्र से 437 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी के अन्तर्गत 4027 मेगावाट क्षमता के कुल 1819 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन सभी में यह सर्वाधिक क्षमता का संयंत्र है। इससे प्रतिदिन औसतन 25 हजार यूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। इससे पहले अजमेर डिस्कॉम में 4.84 मेगावाट क्षमता का सर्वाधिक बड़ा प्लांट था।

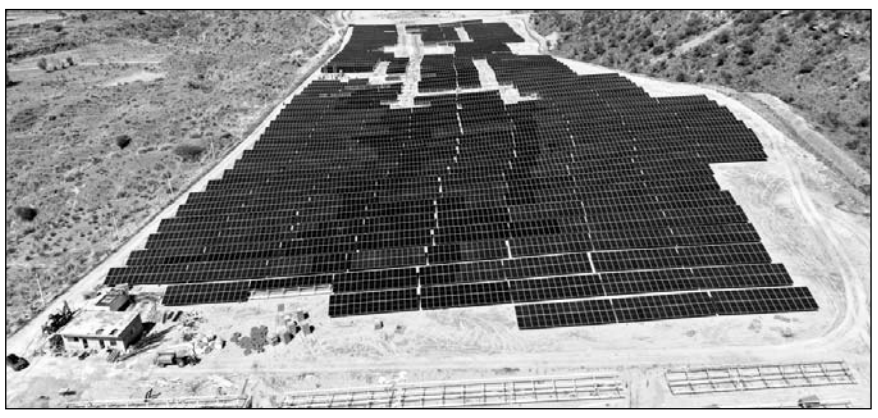

डिस्कॉम्स विकसित करेंगे विकेन्द्रित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली : नागर

जयपुर (कासं)। प्रदेश में डिस्कॉम्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों में बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली विकसित किए जाने की योजना है, जहां पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों अथवा रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्रचुर मात्रा में सरप्लस विकेन्द्रित सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इससे सुबह और शाम के पीक ऑवर्स की विद्युत सप्लाई को मेंटेन करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को विद्युत भवन में बिजली वितरण निगमों कंपनियों की समीक्षा के दौरान इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्युत आपूर्ति को बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टोरेज क्षमता का विस्तार आवश्यक है। शासन सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बैठक में बताया कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा उत्पादित विकेन्द्रित सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडअलोन डिसेन्ट्रलाइज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटरिंग, बिजली छीजत में कमी और गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। नागर ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग से उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग मिल रही है। उन्होंने आरडीएसएस योजना में बिजली छीजत कम करने के लिए और प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया।

'सनातन मूल्यों और सामाजिक समरसता पर चर्चा की जरूरत'

''सनातन संवाद'' में मंदिर प्रबंधन, सामाजिक व्यवस्था एवं जनजागरण पर मंथन हुआ

संस्कृति युवा संस्था की ओर से मंगलवार को जयपुर में सनातन संवाद प्रथम कड़ी का आयोजन हुआ।

जयपुर। संस्कृति युवा संस्था की ओर से मंगलवार को ''सनातन संवाद-प्रथम कड़ी'' का आयोजन जयपुर में हुआ। इस अवसर पर धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। संवाद के दौरान केवल मंदिर प्रबंधन और समाज-परिवार व्यवस्था ही नहीं, बल्कि वर्तमान समय में सनातन मूल्यों की प्रासंगिकता, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण एवं जनजागरण जैसे मुद्दों पर भी गहन मंथन हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। उन्होंने कहा कि ''सनातन संस्कृति हमारी पहचान और समाज की आधारशिला है। इसे सशक्त बनाए रखने के लिए संवाद, जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे संवाद समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।''

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने अपने कहा कि गृहस्थ परंपरा से संचालित मंदिर आज भी समाज में एक सशक्त, जीवंत और अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। चर्चा में यह बात प्रमुख रूप से सामने आई कि परिवार आधारित सेवा परंपरा में श्रद्धा, उत्तरदायित्व, निरंतरता और पारदर्शिता का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है, जो मंदिरों को समाज से सीधे जोड़ता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक मार्गदर्शन, संस्कार निर्माण और सेवा कार्यों के केंद्र भी हैं। संवाद के दौरान मंदिर माफ़ी की ज़मीनों को मुक्त करवाने, वर्तमान समय में सनातन मूल्यों की प्रासंगिकता, परिवार व्यवस्था में आ रहे बदलाव और उनके समाधान, समाज में नैतिकता और संस्कारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता तथा युवा पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के प्रयास पर चर्चा हुई।

आयोजक और संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि समाज में संवाद और समन्वय की आवश्यकता है कि राज्य में आज अनेक स्थानों पर गृहस्थ/परिवार आधारित सेवा परंपरा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।

ट्रैवल ट्रेड के बीच द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार संपन्न

जयपुर। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026 का 15वां संस्करण मंगलवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल ट्रेड के उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह संस्करण इनबाउंड टूरिज़्म को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। आयोजन के दौरान 'बायर्स' और 'सैलर्स' ने व्यापक नेटवर्किंग अवसरों व व्यावसायिक संवाद को लेकर संतोष व्यक्त किया।

इस आयोजन में लगभग 50 देशों से 195 से अधिक प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स (एफटीओ) ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया। एग्जीबिशन में हेरिटेज, वेलनेस, स्पिरिचुअल, वाइल्डलाइफ और एक्सपीरियंस-आधारित टूरिज़्म से जुड़े विविध उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसने विदेशी खरीदारों की विशेष रुचि आकर्षित की।

प्रतिभागियों ने प्रदर्शित गंतव्यों और उत्पादों को अपने-अपने बाजारों में प्रमोट करने की सकारात्मक प्रतिबद्धता भी जताई। एग्जीबिशन के दो दिनों के दौरान मेजबान राज्य राजस्थान सहित ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्य पर्यटन बोर्ड्स के पवेलियंस ने बायर्स का विशेष ध्यान आकर्षित किया। जहां राज्यों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और अनुभव-आधारित पर्यटन ऑफरिंग्स को प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया। इसके साथ ही लग्ज़री एवं हेरिटेज होटल चेन, रिसॉर्ट्स, एडवेंचर और वाइल्डलाइफ ऑपरेटर्स, वेलनेस सेंटर्स तथा ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी ने इस मंच को नए व्यावसायिक अवसरों, निवेश संभावनाओं व दीर्घकालिक साझेदारियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित किया। जीआईटीबी के अंतिम दिन जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर विदेशी टूर ऑपरेटर्स के लिए प्रदर्शित विश्व की प्रतिष्ठित लग्ज़री ट्रेनों में शुमार 'द पैलेस ऑन व्हील्स' प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने ट्रेन का विस्तृत अवलोकन किया और इसकी भव्यता, शाही सजावट और विश्वस्तरीय सुविधाओं की सराहना की। ट्रेन के अंदर उपलब्ध राजस्थानी विरासत से प्रेरित इंटीरियर्स, लग्ज़री केबिन, डाइनिंग सुविधाएं और ऑनबोर्ड सेवाओं ने विशेष रूप से प्रभावित किया।